The banks have been advised by the NABARD to conduct cent percent verification of the relief provided by them and to furnish revised claims after excluding the portion relating to ineligible beneficiaries. Release of further amount is subject to receipt of final claims by NABARD from the above banks in the matter.

Approval to foreign investment proposals

3463. SHRI ASHIS SEN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the number of foreign investment proposals that have since been approved by Government following liberalised policy; and

(b) whether such approvals relate to essential items ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Since the announcement of New Industrial Policy, 1301 approvals for foreign direct investment have been issued till the end of February, 1993 for a total investment of Rs. 6686.82 millions. Over 80% of the approvals for foreign investment are in high priority areas (i.e. areas mentioned in Annex. III of the statement on Industrial Policy dated 24-7-91.)

Steps to reduce deficit

3464. SHRI H. HANUMANTHAPPA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Statesman recently that Government expects its interest payments to go up by Rs. 6,000 crores next year making its task of reducing the fiscal deficit further during 1993-94 budget much more difficult; and

(b) if so, what steps are proposed to be taken by Government to find out the alternative to reduce the fiscal deficit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) As shown in the Budget documents of the Central Government for 1993-94, presented to the House on 27-2-93, Government's total interest payments next year are estimated at Rs. 38000 crore. These represent an increase of Rs. 5538 crore over the Revised estimates 1992-93 on this account. It has, however, been possible to reduce the fiscal deficit as a percentage of estimated GDP in 1993-94, through a combination of measures to contain overall non-plan expenditure, excluding interest payments, and improve tax and non-tax revenue receipts.

फिल्म उद्योग में काले धन का प्राक्कलन

3465. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग में काले धन के बारे में न तो कोई आधिकारिक प्राक्कलन किया गया है और न ही कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) फिल्म उद्योग में काले धन का प्राक्कलन और मूल्यांकन करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ऐसे अनुमान लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति प्रतीत नहीं होती है । राष्ट्रीय जन वित्त एवं नीति संस्थान ने वर्ष 1985 में "भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलुओं" पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की थी । इस अध्ययन में अवैध अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है तथा फिल्म उद्योग में अवैध

धन के कतिपय पहलू का भी उल्लेख किया है । उन्होंने उन 20 क्षेत्रों की सूची दी है, जिसमें अवैध धन सृजित होता है और उन पांच क्षेत्रों के सम्बंध में प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं, जिनके लिए प्रतिवादियों ने अवैध धन के सृजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में समझा । इस सम्बंध में फिल्म उद्योग को तीसरा अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है । यद्यपि अवैध धन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी सरकार इस उद्योग में अवैध धन के सृजन की रोकथाम के लिए आवश्यक सांविधिक एवं प्रशासनिक उपाय करती है । आयकर अधिनियम की धारा 44-एए में उपबंध किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत कारोबार करने वाले हर व्यक्ति के लिए कानून द्वारा निर्धारित लेखा-पुस्तिकाओं को रखना एवं उनको बनाए रखना अपेक्षित है तथा कर निर्धारणों की छानबीन में इनकी जांच-पड़ताल की जाती है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फिल्मी कलाकारों, कैमरामैन, निदेशकों, आदि को व्यावसायिकों के रूप में अधिसूचित किया है, जिनसे धारा 44-एए के अन्तर्गत लेखा-पुस्तिकाओं को बनाए रखना अपेक्षित है । इन व्यक्तियों के कर निर्धारण के बेहतर निपटान के लिए विशिष्ट फिल्म परिमण्डल भी सृजित किए गए हैं और इन मामलो में कर अपवंचन को मालूम किया जा सके । फिल्म निर्माताओं द्वारा 5,000/- रु० से अधिक के भुगतान के विवरण पत्र को उसी समय प्रस्तुत करने के बारे में धारा 285बी में सांविधिक उपबंध भी बनाए गए हैं । इसकी जांच पड़ताल कर-निर्धारणों की छानबीन के समय की जाती है । आयकर जांच खण्ड 10,000/- रु० से अधिक के ऐसे भुगतानों का है, प्रतिसत्यापन भी करता है । तलाशी, सर्वेक्षण तथा अन्य जांच-पड़ताल के माध्यम से इन मामलों में, जब कभी कर-अपवंचन की कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, कार्यवाहियां भी की जाती हैं ।

मितव्ययिता उपायों के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना

3466. **श्री रामसिंह राठवा** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय मंत्रालयों ने मितव्ययिता उपायों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने पूर्वोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) व्यय में किफायत बरतने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को करना होता है । इन अनुदेशों के उल्लंघन का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

प्रत्यक्ष करों की वसूली संबंधी अपीलों का निपटान ।

3467. **श्री रामसिंह राठवा** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष करों की वसूली सम्बन्धी अपीलों के निपटान के कार्य की गति असंतोषजनक है ।